



राज्य के 2.25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से हुए बाहर



सतत विकास लक्ष्य पर आयोजित कार्यशाला के समापन सत्र को संबोधित करती अपर मुख्य सचिव डा. एन विजयलक्ष्मी • सी : विभाग ।

राज्य ब्यूरो, जागरण • षटना: योजना एवं विकास विभाग की अपर मुख्य सचिव डा. एन विजयलक्ष्मी ने कहा कि राज्य की योजनाओं का 'सतत विकास लक्ष्य' के साथ समन्वय अत्यंत आवश्यक है। जिससे समावेशी, सतत एवं संतुलित विकास सुनिश्चित किया जा सके। वे गुरुवार को सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) पर आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला के समापन सत्र को संबोधित कर रही थीं।

उन्होंने बताया कि बिहार सरकार ने वर्ष 2017 में एसडीजी विजन दस्तावेज तैयार कर सभी विभागों की योजनाओं एवं कार्यक्रमों को सतत विकास के लक्ष्यों से जोड़ा है।

राज्य स्तर पर 334

अपर मुख्य सचिव डा. एन विजयलक्ष्मी ने कहा, लक्ष्य के साथ योजनाओं का समन्वय जरूरी

संकेतकों का एक व्यापक ढांचा विकसित किया गया है, जिससे योजनाओं की प्रगति की नियमित निगरानी एवं मूल्यांकन किया जा रहा है। अपर मुख्य सचिव ने कहा कि बिहार ने एसडीजी संकेतकों के आधार पर उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की है।

162 प्रमुख संकेतकों के विश्लेषण में लगभग 72 प्रतिशत संकेतकों में सुधार हुआ है, जो राज्य की मजबूत नीतिगत प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने बताया कि 15 में से आठ लक्ष्यों पर राज्य संतोषजनक प्रगति कर रहा है, जबकि अन्य लक्ष्यों पर भी निरंतर प्रयास जारी हैं। उन्होंने कहा कि बिहार का एसडीजी स्कोर वर्ष 2018 के 48 से बढ़कर 2023-24 में 57 हो गया है।

स्वच्छ जल एवं स्वच्छता के क्षेत्र में बिहार ने 98 अंक प्राप्त कर देश में तीसरा स्थान हासिल किया है। राज्य ने बहुआयामी गरीबी में उल्लेखनीय कमी लाते हुए लगभग 2.25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है।